



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोच्चिन-682009
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468
DID No. 2835100

F.No.CUS/APR/MISC/3595/2021-A/GR

दिनांक Dated. 16.09.2021

व्यापार सुविधा सं. TRADE FACILITY NO.15/2021

व्यापार के सदस्यों का ध्यान सीबीआईसी परिपत्र संख्या 14/2021-सीमा शुल्क दिनांक 07.07.2021, संख्या 28/2020-सीमा शुल्क दिनांक 05.06.2020, संख्या 40/2020-सीमा शुल्क दिनांक 04.09.2020, संख्या 45/2020-सीमा शुल्क दिनांक 12.10.2020 और संख्या 55/2020-सीमा शुल्क दिनांक 17.12.2020, की ओर आकर्षित किया जाता है। जो दिनांक 31.10.2020 से प्रभावी फेसलेस असेसमेंट(मूल्यांकन) पैन इंडिया के रोल आउट हैं और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ प्रक्रियाओं को स्पष्ट/सुव्यवस्थित करने का विवरण देते हैं।

Kind attention from members of Trade is invited to CBIC Circulars No. 14/2021-Customs dated 07.07.2021, No. 28/2020-Customs dated 05.06.2020, No.40/2020-Customs dated 04.09.2020, No.45/2020-Customs dated 12.10.2020 and No. 55/2020-Customs dated 17.12.2020, which put together detail the roll out of Faceless Assessment pan India w.e.f. 31.10.2020 and clarify/streamline certain processes for its effective implementation.

2. इसके अलावा, बोर्ड ने हाल ही में फेसलेस मूल्यांकन के कार्यान्वयन की व्यापक समीक्षा की है और आयातित सामानों के मूल्यांकन और सीमा शुल्क निकासी की गति में तेजी लाने के लिए आवश्यक आगे के उपायों पर विचार किया है। बोर्ड ने पाया कि तेजी से आकलन, आकलन में अनामिकता और आकलन में एकरूपता के संदर्भ में फेसलेस असेसमेंट के उद्देश्यों को पूरा किया गया है। हालांकि, बोर्ड का मानना है कि अब भी सुधार की गुंजाइश है जो संभावित रूप से मूल्यांकन और सीमा शुल्क निकासी की गति को पर्याप्त वृद्धि की ओर अग्रसर करेगा, साथ ही व्यापार के साथ इंटरफेस(अंतर्व्यवहार) को कम करने के उद्देश्य से मूल्यांकन और अनामिकता में एकरूपता को और बढ़ाएगा।

Further, the Board has recently comprehensively reviewed the implementation of Faceless Assessment and deliberated on the further measures required for expediting the pace of assessment and Customs clearance of imported goods. Board finds that by and large the objectives of Faceless Assessment in terms of expeditious assessments, anonymity in assessments and uniformity in assessments have been met. However, Board observes that there is even now scope for improvement which would potentially lead to a substantial increase in the pace of assessments and Customs clearance, while further enhancing the uniformity in assessments and anonymity with a view to reduce interface with the trade.

3. तदनुसार, बोर्ड ने सीमा शुल्क फेसलेस मूल्यांकन और निकासी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित उपायों को लागू करने का निर्णय लिया:

Accordingly, Board has decided to implement the following measures in the Customs Faceless Assessment and clearance processes:

3.1 **सुविधा स्तरों में वृद्धि:** बोर्ड ने पहले आयात में सुविधा स्तरों की समीक्षा की और परिपत्र संख्या 39/2011-सीमा शुल्क दिनांक 02.09.2011 के माध्यम से निर्णय लिया कि, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के लिए सुविधा लक्ष्य 80%, बंदरगाहों के लिए 70% और आईसीडी के लिए 60% होना चाहिए। तब से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के साथ-साथ मौजूदा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए विभिन्न पहल किए गए हैं। परिणामस्वरूप, मई 2021 के लिए सभी सीमा शुल्क स्टेशनों में अखिल भारतीय औसत सुविधा स्तर 77% होने के साथ समग्र औसत सुविधा स्तर पहले ही इन स्तरों से अधिक हो गए हैं। बोर्ड यह भी नोट करता है कि मशीन लर्निंग और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग अब आरएमएस को जोखिम भरे खेपों को अधिक सटीक रूप से लक्षित करने में सक्षम बनाता है जिससे एफएजी द्वारा मूल्यांकन के लिए बिल ऑफ एंट्री की कम संख्या पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सके। इस प्रकार, बोर्ड ने निर्णय लिया है कि 15.07.2021 से प्रभावी सभी सीमा शुल्क स्टेशनों में आरएमडी से संबंधित सुविधा स्तर को 90% तक बढ़ाया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि, किसी भी बिल ऑफ एंट्री के अंतर्विरोध में यादृच्छिकता के तत्व को आरएमएस द्वारा बरकरार रखा जाएगा। इस उपाय से जोखिम भरे आयातों पर अधिक ध्यान देने के साथ गैर-जोखिम वाले आयातों की तेजी से निकासी सक्षम होने की उम्मीद है, ताकि राजस्व सुरक्षित रहे। उपरोक्त परिपत्र को तदनुसार संशोधित किया जाता है।

Enhancement of facilitation levels: Board has earlier reviewed the facilitation levels in imports and vide Circular No. 39/2011-Customs dated 02.09.2011 decided the facilitation targets should be 80% for Air cargo Complexes, 70% for Seaports and 60% for ICDs. Various initiatives have since been taken to leverage technology as well as simplify extant procedures. As a result, the overall average facilitation levels have already exceeded these levels with the All-India average facilitation level across all Customs stations being 77% for May 2021. Board also notes that the use of machine learning and the other state of art technologies now enables RMS to more precisely target the risky consignments thereby enabling more focussed attention on lesser number of Bills of Entry for assessment by the FAGs. Thus, Board has decided that w.e.f. 15.07.2021 the facilitation level across all Customs stations would be increased to 90% relating to RMD. It is clarified that the element of randomness in interdiction of any Bill of Entry would be retained by RMS. This measure is expected to enable faster clearance of non-risky imports with enhanced focus on risky imports, so that revenue remains safeguarded. The aforementioned circular stands modified accordingly.

3.2 **डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी) को बढ़ाना:** परिपत्र संख्या 29/2019-सीमा शुल्क दिनांक 05.09.2019 आयातकों द्वारा डीपीडी का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करता है। तब से बिल ऑफ एंट्री की अग्रिम फाइलिंग सहित कई उपायों ने आयात कार्गो के लिए तेजी से टर्न-अराउंड समय को प्रशस्त किया है। सुविधा स्तरों को बढ़ाने का वर्तमान निर्णय भी इसी दिशा में एक कदम है। हालाँकि, जहाँ सुविधा स्तर ऊपर जा रहे हैं, वहीं DPD का स्तर उसी के अनुरूप नहीं बढ़ रहा है। यह प्राथमिक रूप से इसलिए है क्योंकि वर्तमान नीति में एक इकाई आधारित डीपीडी होती है जबकि सुविधा स्तर प्राथमिक रूप से बिल ऑफ एंट्री से जुड़ी हुई हैं। तदनुसार, तेजी से सीमा शुल्क निकासी के साथ-साथ बंदरगाहों की भीड़भाड़ को कम करने के लिए डीपीडी को बढ़ाने के लिए, बोर्ड ने इकाई आधारित डीपीडी से बिल ऑफ एंट्री आधारित डीपीडी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। संक्षेप में, उक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए, बोर्ड ने निर्णय लिया है कि, एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, सभी अग्रिम बिल ऑफ एंट्री, जो पूरी तरह से सुविधाजनक हैं (मूल्यांकन और/या परीक्षा की आवश्यकता नहीं है) को डीपीडी की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि, यह सुविधा एईओ ग्राहकों के लिए विस्तारित इकाई आधारित डीपीडी की वर्तमान प्रणाली के अतिरिक्त है। हालांकि, जिस इकाई के बिल ऑफ एंट्री को डीपीडी के लिए सुविधा प्रदान की गई है, उसे वास्तविक डिलीवरी लेने के लिए बंदरगाहों/टर्मिनलों/अभिरक्षकों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा। इसके अलावा, बंदरगाहों/टर्मिनलों/अभिरक्षकों द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग को अनुकूलित करने के लिए, आईसगेट कार्गो के आगमन पर बंदरगाहों/टर्मिनलों/अभिरक्षकों को भेजे जा रहे इलेक्ट्रॉनिक संदेश को संशोधित करेगा, साथ ही डीपीडी के साथ प्रदान किए गए (या इसके लिए तैयार) आईईसी विवरण के साथ कंटेनरों को चिह्नित करेगा। फ्लैग जहाँ भी लागू हो, विशिष्ट कंटेनरों की स्कैनिंग की आवश्यकता को भी इंगित करेगा। यह प्रवेश के चरण में इन कंटेनरों के स्टैकिंग और आवाजाही में

कुशल योजना की सुविधा के लिए किया जाएगा और इस प्रकार यह उनके टर्न-अराउंड समय में तेजी लाएगा। इसी तरह का संदेश आयातक/सीमा शुल्क ब्रोकर को भेजा जाएगा।

Enhancing Direct Port Delivery (DPD): Circular No.29/2019-Customs dated 05.09.2019 stipulates the eligibility criteria for availment of DPD by the importers. Since then a number of measures including advance filing of Bill of Entry have led to quicker turn-around time for the import cargo. The present decision to enhance the facilitation levels is also a step in this direction. However, while facilitation levels are going up, the DPD levels are not rising commensurately. This is primarily because the present policy is to have an entity based DPD while facilitation levels are linked primarily to Bills of Entry. Accordingly, in order to enhance DPD for faster Customs clearances as well as de-congestion of ports, Board has decided to shift from entity based DPD to a Bill of Entry based DPD. In short, in partial amendment to the said circular, Board has decided that, as a general principle, all the advance Bills of Entry which are fully facilitated (do not require assessment &/or examination) would be granted the facility of DPD. It is clarified that, this facility is over and above the present system of entity based DPD extended to AEO clients. However, the entity whose Bill of Entry has been facilitated for DPD would be required to adhere to the requirements of the ports/terminals/custodians for taking physical delivery of the container. Further, to optimise the ground handling by the ports/terminals/custodians, the ICEGATE shall modify the electronic message being sent to the ports/terminals/custodians on arrival of the cargo, to additionally flag the containers granted (or ready for) DPD along with IEC details. The flag would also indicate the requirement of scanning of specific containers, wherever applicable. This would be done at the stage of Entry Inwards to facilitate efficient planning in stacking and movement of these containers and thus quicken their turn-around time. Similar message would be sent to the importer/Customs Broker.

3.3 परीक्षा आदेशों का स्वचालित सृजन: एकरूपता बढ़ाने और परीक्षा के आदेशों को कारगर बनाने के लिए, बोर्ड ने देश भर के सभी सीमा शुल्क स्टेशनों पर आरएमएस निर्मित एकरूप परीक्षा आदेश शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, परिपत्र संख्या 45/2020-सीमा शुल्क दिनांक 12.10.2020 के पैरा 2.3 के अनुसार सामान्यतः प्रथम जाँच की आवश्यकता वाली मर्चों के आयात को अब प्रथम जाँच परीक्षा के लिए सीधे शेड में भेजा जाएगा। ऐसे पहले चेक बिल ऑफ एंट्री को अब निर्धारण के लिए एफएजी को भेजा जाएगा, जब सीमा शुल्क प्रणाली में शेड अधिकारियों द्वारा पहली चेक परीक्षा रिपोर्ट अपलोड की जाएगी।

Automated generation of examination orders: In order to enhance uniformity and streamline the examination orders, Board has decided to introduce RMS generated uniform examination orders at all Customs stations across the country. Further, the imports of items which ordinarily warrant First Check as per para 2.3 of Circular No.45/2020-Customs dated 12.10.2020 would now be directly routed to the shed for First Check examination. Such First Check Bills of Entry will now be referred to the FAG for assessment only after a First Check examination report has been uploaded by the Shed Officers in the Customs system.

3.4 अनामिक(गुप्त) एस्केलेशन: बड़े पैमाने पर मूल्यांकन में देरी से संबंधित व्यापार की शिकायतों को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए, डीजी सिस्टम्स जल्द ही आइसगेट पर एक अनामिक एस्केलेशन मैकेनिज्म(प्रणाली) (एईएम) का संचालन करेगा, जो आयातकों/सीमा शुल्क ब्रोकरों को एक विलंबित बिल ऑफ एंट्री, जो मूल्यांकन या परीक्षा के लिए लंबित हो सकता है को तत्काल मंजूरी की अपनी आवश्यकता को सीधे पंजीकृत करने के लिए सशक्त करेगा। अन्यो के साथ एईएम की विशेषताओं में शामिल होंगे:

Anonymised escalation: To better address the grievances of trade relating largely to delays in assessment, DG Systems shall soon shortly operationalise an Anonymized Escalation Mechanism (AEM) on ICEGATE which would empower importers/Customs Brokers to directly register his/her requirement of expeditious clearance of a delayed Bill of Entry, which may be pending for assessment or examination. The features of the AEM would include, amongst others:

- i. 1 कार्य दिवस से अधिक की देरी के मामले में, एक आयातक/सीमा शुल्क ब्रोकर आइसगेट के माध्यम से आईएम शुरू करने में सक्षम होगा या इसके लिए टीएसके से संपर्क कर सकेगा।

In case of delay of more than 1 working day, an importer/Customs Broker would be able to initiate AEM through ICEGATE or approach TSK for the same.

- ii. आईएम संबंधित एफएजी और आयात बंदरगाह के सीमा शुल्क के अपर/संयुक्त आयुक्तों को एक अधिसूचना के साथ संबंधित एफएजी/आयात शेड को स्वचालित रूप से शिकायत भेज देगा।

The AEM will automatically route the grievance to the concerned FAG / Import Shed, with a notification to Additional/Joint Commissioners of Customs of the concerned FAG and Port of Import.

- iii. संबंधित एफएजी को शिकायत का तत्काल निपटान करना आवश्यक है और इसकी निगरानी संबंधित एफएजी/आयात शेड के संबंधित अपर/संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा की जाएगी।

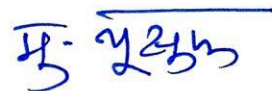
The concerned FAG is required to dispose the grievance promptly and same shall be monitored by the concerned Additional/Joint Commissioner of Customs of the concerned FAG/Import Shed.

- iv. निस्तारण की स्थिति आइसगेट, टी एस के, एफ ए जे के डैश बोर्ड पर तथा सभी संबद्ध अधिकारियों के लिए अद्यतनीकृत की जाएं।

The status of the disposal would be updated on the dashboard of ICEGATE, TSK, FAG and to the concerned officers.

4. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई के या किसी संदेह के होने पर इसे सीमा शुल्क अपर आयुक्त (आयात) के संज्ञान में लाया जाएं।

Any difficulties faced or doubts arising in the implementation of this Circular may please be brought to the ADC (Import).



मो. यूसुफ़ MOHD.YOUSAF
आयुक्त COMMISSIONER

F.No.:CUS/APR/MISC/3595/2021-A/GR

दिनांक Dated:16.09.2021

प्रतिलिपि Copy to :

1. आयुक्त की फाईल Commissioner's File
2. वेबसाइट Website

प्रतिलिपि प्रेषित Copy Submitted to:

मुख्य आयुक्त केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क The Chief
Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs